

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: - 202/2018 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2018/00593

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा राज०  
प्रार्थी

बनाम

1. नगर पालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी महोदय, नगर पालिका  
निम्बाहेड़ा राज०

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

- उपस्थित :- 1- श्री शहादत अली - अधिवक्ता प्रार्थी  
2- श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी - अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01  
3- पेराकर सरकार स्वयं उपस्थित- विपक्षी संख्या 2

:: निर्णय ::

दिनांक :- 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता सं० 605 की आ०नं० 1779 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, आ०नं० 1780 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आ०नं० 1781 रकबा 0.3800 हेक्टेयर, आ०नं० 1782 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, आ०नं० 1783 रकबा 0.1100 हेक्टेयर . आ०नं० 1784 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आ०नं० 1785 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आ०नं० 1786 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, आ०नं० 1787 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, आ०नं० 1908 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, कुल कित्ता 10 कुल रकबा 2.2700 हेक्टेयर स्थित है। इन आराजीयात को आगे वाद वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।



वादग्रस्त आराजीयात निम्बाहेड़ा में निम्बाहेड़ा छोटीसादडी मार्ग पर स्थित है। यह आराजीयात पहले श्री गिरधारी पिता नन्दा गुर्जर निवासी निम्बाहेड़ा के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। जिनके सेटलमेंट से पहले के नम्बर 1322, 1323-1324, 1325, 1326-1327-1328, 1329-1330, 1424 थे। पहले निम्बाहेड़ा छोटीसादडी सडक नही थी केवल पगडंडी थी जिसे सन् 1963-1964 में चौड़ा कर सडक बनाई गई जिसमें गिरधारीलाल गुर्जर की पुरानी आराजी नं० 1322 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से 18 बिस्वा आराजी सडक में ली गई, जिसके नम्बर 2172/1322

सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा

1-5

हुए एवं आराजी नं० 1329-1330 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा मेसे 18 बिस्वा सडक में ली गई जिसके नये नम्बर 2173/1330 हुए और इन आराजी नम्बर 2172/1322 एवं 2173/1330 पर निम्बाहेडा छोटीसादडी सडक बनाई गई, जो उत्तर से दक्षिण बनाई गई जो अभी मौजूद है।

3. सेटलमेंट के पश्चात आराजी नं० 2172/1322 रकबा 18 बिस्वा के नये नम्बर 1778 रकबा 0.23 हेक्टेयर हुआ एवं आराजी नं० 2173/1330 रकबा 18 बिस्वा का नया नम्बर 1788 रकबा 0.23 हेक्टेयर हुआ। यह आराजीयात दोनो बिलानाम सडक रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से यह आराजीयात सडक बिलानाम में दर्ज करने के बजाये नगर पालिका निम्बाहेडा के नाम गे०मु० आबादी में दर्ज कर दी गई, जब कि वहां पर नगर पालिका की कोई आबादी भूमि नहीं है। बल्की सडक है। एवं सडक से लगी पूर्वी दिशा में प्रार्थी व उसके परिवार की आराजीयात है। इसके अलावा यह आराजीयात जो सडक के लिये ली गई थी एवं जिस पर सडक बनाई गई थी वह उत्तर से दक्षिण बनाई गई थी किन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से राजस्व नक्शे में यह आराजीयात उत्तर से दक्षिण के बजाये जहां पर प्रार्थी व उसके परिवार की आराजीयात है वहां पर दो टुकड़ों में पूर्व से पश्चिम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार यह आराजीयात राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी में सडक सरकारी के बजाये गलती से आबादी नगर पालिका दर्ज हो गई है एवं नक्शे में उत्तर से दक्षिण के बजाये पूर्व से पश्चिम प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजीयात के स्थान पर दर्ज कर दी गई है।

4. वाद ग्रस्त आराजीयात पहले गिरधारी पिता नन्दा गुर्जर के खातेदारी की थी जिसके तीन पुत्र लालू, मांगीलाल, एवं हीरालाल थे, और गिरधारी के देहांत के बाद वादग्रस्त आराजीयात उसके तीनों पुत्रों के नाम आई और तीनों का बराबर 1/3-1/3 हिस्सा हुआ। इन तीनों का भी देहान्त हो चुका है। प्रार्थी भैरूलाल स्व० मांगीलाल का एक मात्र पुत्र होकर वादग्रस्त आराजी में उसका 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार मोके पर निम्बाहेडा छोटीसादडी मार्ग सडक से लगी हुई पूर्वी दिशा में प्रार्थी व उसके परिवार की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिनसे नगर पालिका निम्बाहेडा का कोई सम्बंध व सरोकर नहीं है। फिर भी सहवन से जो आराजी नम्बर 1778 एवं 1788 प्रार्थी व उसके परिवार की आराजीयात की जगह नक्शे में दर्ज हो गये है एवं नगर पालिका के नाम दर्ज हो गये है। इस कारण से नगर पालिका निम्बाहेडा वादग्रस्त आराजीयात में नाजायज रूप से हस्तक्षेप करने पर उतारू है साथ ही बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए सडक चौडी करण का कार्य करते हुए नाजायज रूप से प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात में सडक बना रही है जिसका कि उसे कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है।



सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर और रकबा सही है परंतु राजस्व अभिलेखों में किसके नाम से इस कथन की विपक्षी को जानकारी नहीं है प्रार्थी स्वयं साबित करें। पहले आराजी किसके नाम व खातेदारी

पर थी इसकी जानकारी पालिका प्रशासन को नहीं है परंतु निम्बाहेडा-छोटीसादडी प्रारम्भ से बनी हुई है पगडंडी बनीहोना स्वीकार है परंतु सन् 1963 1964 में इस सड़क को चौड़ी कर बनाई हो यह कथन भी स्वीकार नहीं है। आराजी नम्बर 1322 में से 1 बीघा 1 बिस्वा में 18 बिस्वा जमीन ली गई यह कथन स्वीकार नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई पर्टिकूलर आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया है इसलिये यह कथन स्वीकार नहीं है। छोटीसादडी-निम्बाहेडा रोड जो बना हुआ है वो अभी भी उरसी अवस्था में मौजूद है यह कथन स्वीकार है। नगरपालिका क्षेत्र में गुजरने वाली सड़क नगरपालिका की है और उसका मेन्टीनेंस नगरपालिका करती है और सड़क से लगी हुई भूमि मार्गाधिकार का भाग है जो नगर निम्बाहेडा के नागरिकों के लिये आवागमन करने का स्थान है और मार्गाधिकार की भूमि पर नगर पालिका निम्बाहेडा को व्यापक जन हित में निर्माण करने का अधिकार है। शेष कथन स्वीकार नहीं है। गिरधारी पिता नन्दा जी गुर्जर के कितने वारिस है और किसका कितना हिस्सा है इसकी जानकारी पालिका प्रशासन को नहीं है। प्रार्थी स्वयं साबित करे इसलिये जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। नगरपालिका के खातेदारी में जो खसरा नम्बर अंकित है उसको छोड़कर अन्य भूमि से पालिका प्रशासन को कोई लेना-देना नहीं है। सड़क की भूमि के आस-पास संपूर्ण चौड़ाई तक पालिका द्वारा व्यापक जन हित में निर्माण किया जा रहा है प्रार्थी को इस निर्माण को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पालिका प्रशासन के विरुद्ध प्रचलित कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। सुविधा का संतुलन विपक्षी के पक्ष में है। नगर निम्बाहेडा की ओर आने वाली छोटीसादडी वाली रोड को समय पर चुस्त-दुरुस्त नहीं किया गया तो जनसामान्य को भारी क्षति होगी। व्यापक हित में जनता-जनार्दन को कठिनाईयों का सामना करना होगा इसलिये सुविधा का संतुलन विपक्षी के पक्ष में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। प्रार्थी विपक्षी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नहीं है।



सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा

6. विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी भैरूलाल पिता मांगी लाल गुर्जर के साथ मय राजस्व रिकार्ड मोका देखा गया मौके पर मण्डी चौराहे से कच्ची बस्ती की तरफ कृषि मण्डी के साथ-साथ डबल रोड़ है जबकि राजस्व मैप में, रोड़ नहीं दर्शाया गया है और नाही रोड़ में दर्शाया गया है जबकि नगरपालिका क्षेत्र की रोड़ों का खाता संख्या 933 है जो निम्बाहेडा के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी की आराजी नं. देखने पर जाहीर आया की प्रार्थी संयुक्त खाते में हिस्सेदार है जिसकी दो आराजी 1778 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 व 1787 रकबा 0.27 हेक्टेयर किस्म चाही । रोड़ के साथ लगती है जबकि प्रार्थी के 8 आराजीयत मैन रोड़ से पिछे है। मैन रोड़ के आस पास की आराजीयात देखने पर जाहीर आया की जब हम रोड़ से कच्ची बस्ती की तरफ जाते है तब हमारे दाहीनी तरफ की आराजीयात कृषि उपज मण्डी के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि रोड़ व बाई तरफ की आराजीयात नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस कारण रोड़ की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः ऐसा लगता है जब कृषि भूमि का सम्पत्तिवर्तन हुआ है तब सरेन्डर कृषि भूमियों से रोड़ का निर्माण

हुआ है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये नगरपालिका निम्बाहेडा और सर्वे टीम का सहयोग लिया जाना उपेक्षित है।

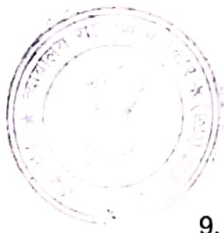
5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विश्लेषण इस प्रकार है-

I. प्रथम दृष्टया मामला- हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी किसी भी प्रकार से नगर पालिका निम्बाहेडा के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

II. अपूरणीय क्षति- किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे है। अपूरणीय क्षति विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थी को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. सुविधा का संतुलन :- किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।



सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेटुक आराजियात हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

-आदेश-

पञ्जावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर जोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संतुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निघारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया



(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा